न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :— 9/2012

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

श्री रामरतन पुत्र जगन्नाथ जाति लोधा निवासी गेहूॅखेडी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1— पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2— श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 4.1.2019

प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेहूॅखेडी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 18/0.16, 22/1 की 0.10, 124/0.15 किता 3/2.01 किस्म वा0 I/गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012—2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम गेहूॅखेडी की भूमि खसरा नम्बर 18/0.16, 22/1 की 0.10, 124/0.15 किता 3/2.01 दिनांक 10.7.1999 को उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा श्री रामरतन पुत्र जगन्नाथ लोधा निवासी गेहूॅखेडी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066—69 मे हैसियत खातेदार श्री रामरतन पुत्र जगन्नाथ जाति लोधा निवासी गेहूॅखेडी के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 22.8.2012 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी इस न्यायालय मे जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है। प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि तहसीलदार छबडा को उक्त रेफरेंस पेश करने का कोई अधिकार नही है। यह मामला अप्रार्थी को आवंटन से संबंधित है। आवंटन के सम्बन्ध मे अपील ही की जा सकती है या नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियमन के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार आवंटन के तहत खोले गये इन्तकाल व दी गई खातेदारी के विरूद्व रेफरेंस की कार्यवाही नही की जा सकती। आवंटित भूमि पर खातेदारी दी जा चुकी है। खातेदारी दी गई भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा सकती। आवंटन व नियमन की कार्यवाही मे तहसीलदार स्वयं पक्षकार होता है। वह स्टेट को रिप्रजेन्ट करता है। इसलिए उसे कार्यवाही पेश करने का कोई अधिकार नही है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम गेहॅूखेडी जिसके खसरा नम्बर 12 की रकबा 0.06 है। जो किस्म गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही निरस्त योग्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने दिये है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम गेहॅूखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 18/0.16, 22/1 की 0.10, 124/0.15 किता 3/2.01 भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 4.1.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां